

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

कन्हैया लाल साह,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार(ले. एवं ह.),
महालेखाकार (ले. एवं ह.) का कार्यालय,
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक 26 फरवरी, 2019

विषय:- वेतन पुनरीक्षण के उपरान्त प्राप्त प्रोन्नति के आधार पर वेतन निर्धारण हेतु विकल्प चयन के संबंध में।

प्रसंग:- व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या-4-13/17-आई सी/ई-11।ए दिनांक 12.12.2018 पर आधारित श्री राहुल सिंह, भा0प्र0से0(बी एच: 96), सचिव, व्यय, वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-06/Secy (E), दिनांक 15.02.2019.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक आवेदन (श्री राहुल सिंह, भा0प्र0से0-1996 से प्राप्त प्रसंगाधीन आवेदन) की अनुलग्नक सहित छाया प्रति संलग्न करते हुए निदेशानुसार कहना है कि व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या-4-13/17-आई सी/ई-11।ए दिनांक 12.12.2018 के आलोक में पुनरीक्षित वेतन के तहत दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से हुए पुनरीक्षण को दिनांक 01.07.2016 के प्रभाव से पुनर्निर्धारित किये जाने का अनुरोध श्री राहुल सिंह, भा0प्र0से0(1996), सचिव, व्यय, वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा अनुलग्न आवेदन में किया गया है।

व्यय

2. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के संलग्न कार्यालय ज्ञापन दिनांक 12.12.2018 द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा(आर पी) नियमावली, 2016 के नियम-6(4) के प्रावधान को शिथिल करते हुए केन्द्र सरकार के उन सेवकों, जिन्होंने पूर्व में नियम-6(4) के तहत वेतन पुनरीक्षण के विकल्प का प्रयोग किया था, को नियम-5 और 6 के तहत आरंभिक विकल्प को आलोच्य ज्ञापन के निदेशों अनुरूप उक्त ज्ञापन के निर्गमन से तीन माह के अन्दर पुनरीक्षित कराने का अवसर प्रदान किया गया है।

3. अतः अनुरोध है कि श्री राहुल सिंह, भा0प्र0से0(1996), सचिव, व्यय, वित्त विभाग, बिहार, पटना के संलग्न आवेदन एवं अन्य सदृश आवेदनों पर समुचित कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक—यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक- 1/वि0-1038/2015-सा0प्र0-...../पटना-15, दिनांक फरवरी, 2019
प्रतिलिपि:-श्री राहुल सिंह, भा0प्र0से0(96), सचिव, व्यय, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- 1/वि0-1038/2015-सा0प्र0-~~26.58~~ /पटना-15, दिनांक 26 फरवरी, 2019
प्रतिलिपि:-भा0प्र0से0(बिहार संवर्ग) के सभी पदाधिकारियों को व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या-4-13/17-आई सी/ई- 11।।ए दिनांक 12.12.2018 की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



26.2.19

सरकार के अवर सचिव।

206

No. 4-13/17-IC/E-III A
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

New Delhi, the 12th, December, 2018

Off ice Memorandum

Subject: Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016 - opportunity for revision of option to come over to revised pay structure

The undersigned is directed to invite attention to Rules 5 & 6 of the CCS (RP) Rules, 2016 regarding exercise of option to come over to the revised pay structure effective from 1.1.2016 as notified by the CCS(RP) Rules, 2016 and to say that the said option was to be exercised within 3 months of the date of notification, i.e., 25.7.2016, of the said Rules. The Rule 6(4) thereof provides that the option once exercised shall be final.

2. The Staff Side of the National Council (JCM) has requested that employees may be given another opportunity to re-exercise their option in view of certain hardships caused to certain employees. A number of references have also been received in this Ministry, proposing that the affected employees may be given an opportunity to re-exercise their option.

3. The matter has been considered and the President is pleased to decide that in relaxation of the stipulation contained in Rule 6(4) of CCS(RP) Rules, 2016, the Central Government employees, who have already exercised their option to come over to the revised pay structure as notified by the CCS(RP) Rules, 2016, shall be permitted another opportunity to revise their initial option in terms of Rules 5 & 6 thereof. The revised option shall be exercised within a period of 3 months from the date of issue of these orders. The option once exercised in terms of these orders shall be final and shall not be liable to any further change under any circumstances. All other terms and conditions as laid down in the said Rules 5 and 6 shall continue to be applicable.



205

- 2 -

4. It is obvious that in respect of those employees who have already exercised option to come over to the revised pay structure from 01.01.2016 itself or in whose case the revised pay structure took effect from 01.01.2016 and who re-exercise their option under these orders to come over to the revised pay structure from a date subsequent to 01.01.2016 as per Rule 5 of CCS (RP) Rules, 2016, the arrears on account of revised pay already drawn by them from 01.01.2016 up to the date from which they now opt to come over to the revised pay structure shall be recovered.

5. In their application to the employees serving in IA&AD, these orders were issued after consultation with the Comptroller and Auditor General of India.



(Amar Nath Singh)
Director

To,

1. All Ministries/Departments of the Government of India (As per standard distribution list)
2. Guard File
3. NIC with the request that the same be posted on the website of Ministry of Finance, Department of Expenditure.